

प्रेषक,

कुवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक³⁾ 31 जुलाई, 2006

विषय:- सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनावटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यों हेतु आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के शासनादेश संख्या 380 /XVIII(2) /2006 दिनांक 18.05.2006 द्वारा उत्तरांचल जल संस्थान को अवमुक्त रु0 8.75 करोड़ की धनराशि के व्यय हेतु शर्तों के निर्धारण शासनादेश संख्या 482 /XVIII(2) /2006 दिनांक 13.06.2006 में किया गया है।

2— सूखा राहत मद में उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 8.75 करोड़ के उपयोग के संदर्भ में दिनांक 12.07.2006 को सचिव पेयजल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में उत्तरांचल जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्यों के प्रावक्कलन छोटी-छोटी लागत के एवं बहुत अधिक संख्या में हैं, जिसका शासन स्तर पर टी०४०सी० से परीक्षण कराने की प्रक्रिया में काफी समय लगने की समावना को देखते हुये सूखा राहत तथा दैवीय आपदा मद में समय से उपयोग किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा इस प्रकार के प्रावक्कलनों की स्वीकृति का अधिकार क्षेत्रीय स्तर पर दिये जाने का अनुरोध किया गया।

3— अतः वर्णित स्थिति में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.06.2006 में आधिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित “क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यों हेतु आगणन गठित कर सक्षम स्तर से सत्यापित एवं प्रमाणित किया जायेगा

तथा तकनीकी परीक्षणोपरान्त टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत धनराशि ही व्यय की जायेगी। के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाये।

‘ज्ञातिग्रस्त पेयजल योजनाओं के सम्मत कार्य हेतु आगणन गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी परीक्षण करा कर स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी तथा समझ स्तर से तकनीकी परीक्षण के पश्चात रु 5.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं 10.00 लाख तक की धनराशि मण्डलायुक्त तथा 10.00 लाख से अधिक के आगणन प्रस्तावों पर टी०ए०सी० की संस्तुति के पश्चात ही स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी।’

5— उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 13.06.2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा इसकी शेष अन्य शर्त यथावत् रहेगी।

6— यह आदेश आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय,

(कुंवर सिंह),
अपर सचिव

पृ०स०— १५२० (1) / उन्तीस(2) / 2006 तददिनांकित

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओवैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. सयुक्त सचिव, एन०डी०एम०, प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल, पौडी / नैनीताल।
4. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. वित्त अनुभाग 2/5
7. कोषधिकारी, पौडी / नैनीताल।
8. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
9. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
11. राज्य सूचना अधिकारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, गढ़वाल / कुमाऊ।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

१०५
(कुंवर सिंह),
अपर सचिव